RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 13 MAY TO 19 MAY 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 38 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

उद्योगों की विद्युत समयस्याओं पर बिजली कंपनी सीएमडी के साथ बैठक Page 2

प्लास्टिक उद्योगों को मिले उत्पादन की अनुमति Page 3

आत्मनिर्भर भारत पैकेज: सरकार की एक साल की कुल कमाई से भी ज्यादा हैं 20 लाख करोड़ रुपये Page 5

editoria!

श्रम सुधार का रास्ता

कोरोना वायरस की वजह से बेजान पड़ी अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए देश में श्रम सुधारों का रास्ता अपनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत राज्य सरकारों की तरफ से हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात की सरकारों ने इस संबंध में पहलकदमी की और फिर असम, महाराष्ट्र, ओडिशा और गोवा ने भी इस दिशा में कुछ अहम फैसले किए, जिनका दूरगामी असर हो सकता है। बिहार और कुछ अन्य राज्य भी इस बारे में गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार करने को लेकर जो अध्यादेश जारी किया है उसमें कहा गया है कि राज्य में अगले तीन सालों के लिए 35 बड़े श्रम कानून लागू नहीं किए जाएंगे। हालांकि, महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून अभी बने रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने कुटीर उद्योगों और छोटे कारोबारों को रोजगार, रजिस्ट्रेशन और जांच से जुड़े विभिन्न जटिल श्रम नियमों से छुटकारा देने की पहल की है, साथ ही कारखानों और कार्यालयों में काम कराने की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है। हफ्ते में 72 घंटे तक कार्य कराए जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए श्रमिकों को ओवर टाइम देना होगा। असम सरकार ने भी काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए हैं। उसने फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट नीति अपनाई है। कंपनियां अब ठेकेदारों की मदद लेने के बजाय सीधे निश्चित अवधि के लिए श्रमिकों की नियुक्ति कर सकती हैं, लेकिन उन्हें अन्य मजदूरों की तरह तमाम सामाजिक सुरक्षा देनी होगी। देश की अर्थव्यवस्था में सुस्ती दरअसल कोरोना के प्रकोप से पहले ही आने लगी थी और कई विशेषज्ञों की राय थी कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए लेबर रिफॉर्म करने होंगे। मजदूरों से जुड़े मौजूदा कानूनों में से कई इंदिरा गांधी के दौर में बनाए या संशोधित किए गए थे, लेकिन व्यवहार में उनका विपरीत असर पड़ा। इनसे लाइसेंस राज को बढ़ावा मिला, जिसने उद्यमियों के लिए कई तरह की मुश्किलें पैदा कीं। लेबर कानूनों की सख्ती के कारण ही कई उद्यमियों ने दूसरे देशों का रुख किया। बहुतों ने तो कारोबार डूबने के डर से उद्यम लगाने ही बंद कर दिए। सचाई यह है कि केंद्र और राज्यों के करीब 200 कानूनों की वजह से आज मजदूर दर-दर भटक रहे हैं। ये कानून कागज पर भले ही कामगारों के हितों की रक्षा करते दिखते हैं, पर वास्तव में ये संगठित क्षेत्र में उनके रोजगार की संभावना को ही समाप्त कर देते हैं। यही वजह है कि आज 90 फीसदी रोजगार असंगठित क्षेत्र में हैं। इन्हीं की वजह से भारत के ज्यादातर उद्यम छोटे से बड़े नहीं हो पाते। बहरहाल, अब राज्यों की पहल से माहौल बदलेगा। आज की तारीख में जरूरत इस बात की है कि बड़े पैमाने पर निवेश हो, उद्योग-धंधे शुरू हों और लोगों को रोजगार मिले। उम्मीद है कि इन उपायों से राज्यों को तो लाभ होगा ही, पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा।

कच्चे तेल में गिरावट

नई दिल्ली। एजेंसी

अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार बढ़ने और कोरोना वायरस की संभावित दूसरी लहर के बारे में चिंता से बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। बुधवार को इंटरनेशल मार्केट में कच्चे तेल के बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल होने वाले ब्रेंट क्रूड का भाव 49 सेंट या 1.6 फीसदी गिरकर 29.49 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। मंगलवार को ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 7 फीसदी उछल गया था। वहीं , बुधवार को अमेरिकी क्रूड 41 सेंट या 1.6 फीसदी गिरकर 25.37 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। सुबह 10 बजे के आसपास एमसीएक्स पर कच्चे तेल का मई वायदा भाव 12 या 0.62 फीसदी गिरकर 1936 रुपये प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकन पेट्रोलियम संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार 76 लाख बैरल बढ़ गया है। ओपेक के सबसे बड़े उत्पादक देश सऊदी अरब ने कहा कि वह कच्चे तेल का उत्पादन 10 लाख बैरल रोजाना और घटाएगा। इसके बाद से कारोबारियों ने बड़े पैमाने पर अपने सौदे काटे हैं। सोमवार को, सऊदी अरब ने कहा कि वह अगले महीने कच्चे तेल के उत्पादन में 10 बैरल प्रति दिन की कटौती कर क्रूड उत्पादन 75 लाख बैरल रोजाना पर लाएगा। उधर, कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों का संगठन ओपेक और दूसरे सहयोगी जैसे कि रूस वगैरह मई और जून में कच्चे तेल का उत्पादन 97 लाख बैरल रोजाना कटौती के लिए राजी हुए हैं।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ी

मिलीं और भी कई सौगातें

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना संकट को देखते हुए सकरार ने आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब आईटी रिटर्न 30 नवंबर तक भरा जा सकता है। आमतौर पर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 जुलाई होती है, लेकिन महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए इस साल इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय के इस फैसले को करदाताओं के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। सैलरीड क्लास के लिए 31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख होती है। प्रोफेशनल वर्ग के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर होती है। इस तरह से सैलरीड क्लास को 4 माह की जबकि प्रोफेशनल को 1 माह का एक्सटेंशन मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा के बारे में बुधवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इस संबंध में विस्तार से बताया. उनके साथ वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे। इस मौके पर ठाकुर ने बताया कि सरकार ने कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 नवंबर कर दिया है।

बड़ी राहत

टैक्स में राहत

वित्तमंत्री ने बताया कि डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट की डेडलाइन भी बढ़ाई गई है। अब इसे 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि TDS ,TCS दरों को घटाया गया 25% घटाया गया है, जो कल से लागू हो जाएंगी। इससे TDS और TCS देने वालों को 50,000 करोड़ की राहत होगी। खासकर नॉन सैलरी वालों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, यानी प्रोफेशनल को रीफंड तुरंत दिया जाएगा। वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि रियल स्टेट के लिए फोर्स मेज़र लागू किया जाएगा। जिससे उसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन में समय की राहत मिलेगी। उनका कांट्रेक्ट खत्म नहीं माना जाएगा। 6 महीने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन टाइम बढ़ाया गया है। इसकी तारिख 25 मार्च मानी जाएगी।

कोविड-19 से होटल उद्योग हलकान

जनवरी-मार्च में प्रति कमरा कमाई 29% तक घटी

नयी दिल्ली। कोविड-19 महामारी के चलते देश के 11 बड़े शहरों में होटल उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके

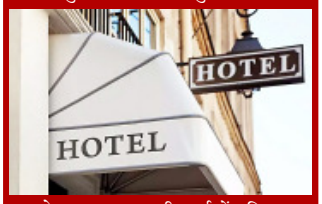

चलते इस साल जनवरी-मार्च में प्रति कमरा कमाई 29 प्रतिशत तक घट गई। जेएलएल इंडिया के मुताबिक 11 शहरों - अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुरुग्राम, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई, पुणे और कोलकाता में- कमरों के भरे होने का स्तर 5-17 प्रतिशत तक गिर गया, जबकि प्रति कमरा आय में 13-29 प्रतिशत तक कमी आई। प्रॉपर्टी सलाहकार जेएलएल इंडिया ने एक रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2020 की पहली तिमाही में घरेलू होटल और आतिथ्य क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। आंकड़ों के मुताबिक सभी 11 शहरों में कमरों के भरे होने और कमरों से कमाई, दोनों में कमी हुई।

उद्योगों की विद्युत समयस्याओं पर बिजली कंपनी सीएमडी के साथ बैठक

न्युनतम शुल्क, बिजली बिलों में छुट सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

देश व्यापी लॉकडाउन के बाद उद्योगों की सबसे बडी समस्या बकाया टैक्स और विद्युत बिल भरने की है। लघु सुक्ष्म और मध्यम उद्योगों के सामने अपने बकाया बिल के साथ बिजली बिलों की न्युनतम राशि भरने की है। जो लॉकडाउन के दौरान उत्पादन ठप्प होने के बाद भी बिल का भुगतान करना होगा। वही अन्य राज्यों में उद्योंगो को राहत देने के लिए बिजली बिल में अगले तीन महीने न्यूनतम चार्ज नहीं लेने, अगले तीन माह का बिल का भुगतान जुलाई माह में बिना किसी पेनल्टी अथवा ब्याज के जमा करने की राहत और इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी अगले पाँच साल के लिए माफ़ करने की पहल की है। इस संबध में सोमवार को विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधी मप्र पश्चिचम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी श्री विकास नरवाल से मिले। इस दौरान उद्योगों के हित में चर्चा करते हुए अनेक मांग और सुझाव दिए गए। विद्युत कंपनी मुख्यालय में हुई इस बैठक में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए चर्चा की गई।

प्रदेश में उद्योगों को बिजली के बिल भरना बडी आर्थिक समस्या के रूप में सामने आ रहा है। लोड के अनुसार आने वाले न्युनतम बिल लॉक डाउन के दौरान लाखों की राशि के हो गए है। ऐसे में बिना राहत पैकेज के उद्योगों का संचालन मुश्किल होगा। सोमवार को मप्र पश्चिचम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मुख्यालय में लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेश गुप्ता, इंडियन प्लास्टपैक फोरम के अध्यक्ष श्री सचिन बंसल, लघु उद्योग भारती के मालवा संभाग सचिव विनित जैन, जिला अध्यक्ष श्री धनंजय चिंचालकर सहित अन्य संगठन के प्रतिनिधी विद्युत वितरण कंपनी के एमडी श्री विकास नरवाल से मिले। इस दौरान बताया गया कि वर्तमान में उद्योग- व्यापार की हालत चिंताजनक है और उद्योगपति आर्थिक रूप से कमजोर । ऐसे में औद्योगिक जगत को शासन-प्रशासन और विभागों के सहयोग अपेक्षित है। इससे उद्योग कारखानें एकबार फिर से प्रारंभ किए जा सकेगें। इस दौरान मांग और सुझाव प्रतिवेदन दिया गया। इसमें प्रदेश ऊर्जा विभाग ने विद्युत उपभोक्ताओं को दिनांक 15 मई या इसके पूर्व तक देय होने वाले सभी देयकों की भुगतान तिथी विस्तारित को आगे बढाने की मांग की गई। साथ ही सभी उपभोक्ताओं के बिलों में जुडने वाली स्थाई न्यूनतम राशि को माफ करने की मांग की गई। प्रदेश के सभी निम्न दाब गैर घरेलू एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं एवं उच्चदाब टैरिफ एचटी उपभोक्ताओं से माह अप्रैल 2020 के देयकों के लिए उनकी संविदा मांग पर लगने वाले स्थाई प्रभार फिक्स चार्ज की वसूली को माफ करने की मांग की गई।

वर्तमान आपात परिस्थितियों को देखते हुए उपभोक्ताओं से केवल वास्तविक खपत का बिल जारी करने और नियत प्रभार एवं न्यूनतम चार्जेस से उन्हें जब तक ऐसी स्थिति रहती है मुक्त रखें का सुझाव दिया गया। प्रतिनिधी मंडल ने बताया कि ऐसा नही होने की स्थिती में अनेकों उद्योग बिलो का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होंगे एवं उद्योगों को स्थाई रूप से बंद करने की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। उद्योग कारखानों में स्थापित विद्युत कनेक्शन के लिए विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा लिया जाने वाला न्यूनतम शुल्क नहीं लिए जाना उचित होगा। प्रतिनिधी मंडल ने बताया कि हमारी जानकारी में आया है कि अन्य राज्यों की सरकारों एवं विद्युत नियामक आयोग द्वारा निम्नलिखित तीन छूट प्रदान की गई है। हम अपेक्षा करते है कि मप्र शासन भी उद्योग हित में इस दिशा में कार्य करेगा। इसमें. बिजली बिल में अगले तीन महीने न्यूनतम चार्ज नहीं लगाया जाएगा। अगले तीन माह का बिल का भुगतान जुलाई माह में लिया जाएगा। बिना किसी पेनल्टी अथवा ब्याज के भरने की छूट देने और इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी अगले पाँच साल के लिए माफ़ की जाने जैस मुद्दे शामिल है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के कई इक्विटी सौदों से कंपनी की रेटिंग सुधरेगी : फिच

नयी दिल्ली। एजेंसी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रस्तावित सात अरब डॉलर के राइट्स इश्यू, जियो मंच में आठ अरब डॉलर के इक्विटी सौदों तथा बीपी पीएलसी के साथ संयुक्त उद्यम में एक अरब डॉलर आने से कंपनी की रेटिंग सुधरेगी। फिच रेटिंग्स ने बुधवार को यह बात कही। फिच रेटिंग्स ने बयान में कहा कि राइट्स इश्यू और इक्विटी सौदे पूरे होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की दीर्घावधि की बीबीबी की स्थानीय-मुद्रा जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग (आईडीआर) में सुधार होगा। फिच रेटिंग्स ने कहा कि रिलायंस की विदेशी मुद्रा आईडीआर (बीबीबी-/स्थिर) रेटिंग देश की ट्रिपल बी- की सीमा की वजह से प्रभावित है। फिच ने कहा कि तेल-से-दूरसंचार क्षेत्र में कार्यरत कंपनी का प्रबंधन मार्च, 2021 तक शुद्ध नकदी की स्थिति को हासिल करने को प्रतिबद्ध है। वह इसे पहले भी हासिल कर सकता है, बशर्ते उसे राइट्स इश्यू और इक्विटी सौदों के लिए नियामकीय और अन्य आवश्यक मंजूरियों 2020 में ही मिल जाएं। कंपनी ने तीन सप्ताह में जियो प्लेटफॉर्म में तीन इक्विटी सौदों की घोषणा की है। इनमें फेसबुक द्वारा 5.7 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा के अलावा सिल्वरलेक पार्टनर्स द्वारा 75 करोड़ डॉलर कानिवेश और विस्ता इक्विटी पार्टनर्स द्वारा डेढ़ अरब डॉलर के निवेश की घोषणा शामिल है।

सरकार के आर्थिक पैकेज की घोषणा से सेंसेक्स 637 अंक की छलांग के साथ 32,000 अंक के पार

मुंबई। एजेंसी

कोरोना वायरस की मार से प्रभावित अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा से बुधवार को शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला थम गया और सेंसेक्स 637 अंक की छलांग के साथ 32,000 अंक के पार निकल गया। दिन में कारोबार के दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स एक समय 1,474.36 अंक ऊंचा चला गया था। हालांकि, बाद में इसने कुछ लाभ गंवा दिया और अंत में यह 637.49 अंक या 2.03 प्रतिशत की तेजी के साथ 32,008.61 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई निफ्टी 187 अंक या 2.03 प्रतिशत की बढ़त के साथ 9,383.55 पर बंद हुआ। कारोबारियों ने कहा कि निवेशक आर्थिक पैकेज के ब्योरे का इंतजार कर रहे हैं। इस वजह से बाजार दिन के उच्चस्तर तक जाने के बाद कुछ नीचे आया। सेंसेक्स की कंपनियों में में एक्सिस बैंक का शेयर सबसे अधिक 7.02 प्रतिशत चढ़ा। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, एलएंडटी, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एमएंडएम और बजाज फाइनेंस में भी तेजी रही। दूसरी ओर नेस्ले इंडिया, सन फार्मा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और भारती एयरटेल 5.38 प्रतिशत तक के नुकसान के साथ बंद हुए। कारोबारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था में नई जान डालने के लिए बड़े आर्थिक प्रोत्साहन की घोषणा से घरेलू निवेशकों की बाजार के प्रति धारणा को बल मिला। मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक प्रोत्साहन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि पैकेज सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 10 प्रतिशत होगा और आत्म-निर्भर भारत अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रेलिगेयर ब्रोकिंग के उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा, ''प्रधानमंत्री द्वारा बहुप्रतीक्षित पैकेज की घोषणा से निवेशकों का उत्साह लौटा। इससे बाजार में उल्लेखनीय बढ़त देखने को मिली। ज्यादातर क्षेत्रों के शेयर अच्छे लाभ के साथ बंद हुए।'' मिडकैप और स्मॉलकैप में 1.97 प्रतिशत तक का लाभ रहा।

बाजार बंद होने के बाद प्रोत्साहन पैकेज का ब्योरा देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) सहित कंपनियों के लिए बिना किसी गारंटी के तीन लाख करोड़ रुपये की ऋण सहायता की घोषणा की। इसके अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को 30,000 करोड़ रुपये की नकदी सुविधा भी देने की घोषणा की गई है। इस बीच, अन्य एशियाई बाजारों में मिलाजुला रुख रहा। चीन का शंघाई कम्पोजिट और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहे। वहीं हांगकांग के हैंगसेंग और जापान के निक्की में गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार नुकसान में कारोबार कर रहे थे। अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में रुपया पांच पैसे की बढ़त के साथ 75.46 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 1.30 प्रतिशत के नुकसान से 29.59 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।

अमेरिका में पाबंदियां तेजी से हटाई गईं तो अधिक मौतें, आर्थिक नुकसान देखने को मिल सकता है : डॉ फॉसी

वाशिंगटन। एजेंसी

अमेरिकी सरकार में कोरोना वायरस पर शीर्ष विशेषज्ञ डॉ. एंथनी फॉसी ने मंगवलार को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर शहर और राज्य घरों में रहने के आदेश तेजी से वापस लेते हैं तो वहां स्थिति बदल सकती है और कोविड-19 से अधिक लोगों की मौत तथा आर्थिक नुकसान देखने को मिल सकता है। फॉसी ने सीनेट की एक समिति और देश को आगाह किया, ''इसका सही में खतरा है और संक्रामक रोग का ऐसा दौर शुरू होगा कि आप उसे काबू नहीं कर पाएंगे।'' दरअसल 24 से अधिक राज्यों ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के पहले कदम के तौर पर लॉकडाउन को हटाना शुरू कर दिया है।

उनका यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख से बिल्कुल अलग है। वैश्विक महामारी की गंभीरता पर जोर देते हुए फॉसी तथा अन्य विशेषज्ञों ने घर से ही कांग्रेस के समक्ष बयान दिया। फॉसी ने सीनेट की स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम और पेंशन समिति को बताया कि अगर लोगों ने फिर से एकत्रित होना शुरू कर दिया तो संक्रमण के नए मामले आना तथा अधिक लोगों की मौत होना निश्चित है।

उन्होंने कहा, ''इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप इसे फैलने से रोकने की कोशिश करोगे तो भी कुछ मामले दिखाई देंगे।'' उन्होंने कहा कि बहुत तेजी से आगे बढ़ने पर इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। गौतलब है कि लॉकडाउन के कारण अमेरिका में तीन करोड़ से अधिक लोगों के बेरोजगार होने के कारण ट्रंप राज्यों को फिर से खोलने पर जोर दे रहे हैं। हाल ही के एक आकलन के अनुसार पाबंदियों में ढील देने वाले 17 राज्य व्हाइट हाउस के अहम मानदंड पर खरे नहीं उतरते हैं यानी वहां नए मामलों या संक्रमित होने की दर में लगातार 14 दिन तक गिरावट नहीं देखी गई।

शहरी क्षेत्र के उद्योगों को अनुमति पत्र वितरित

बस्तियों में भोजन वितरण के लिए 3 हजार लीटर तेल देगा एआईएमपी

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्यप्रदेश के कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और विधायक श्री रमेश मेंदोला ने इंदौर के 8 निर्यात उद्योगों व 70 खाद्य उद्योगों को उत्पादन आरंभ करने के अनुमति पत्र प्रदान किए। अतिथियों द्वारा कोविड-19 के दिशानिर्देशों एवं सुरक्षा-रक्षा योजना संबधित एक पोस्टर का भी विमोचन किया गया। इस पोस्टर को जिसे प्रत्येक कारखाने में लगाया जाएगा।

एआईएमपी अध्यक्ष प्रमोद डफरिया ने बताया कि जिला प्रशासन ने एसोसिएशन के प्रस्ताव पर इंदौर जिले के किला मैदान व सांवेर रोड स्थित 8 निर्यातक एंव 70 शहरी क्षेत्र के खाद्य व कृषि संबधी उद्योगों को अनुमति मिली है। जिनमें अजय स्नेक्स, इटालियन एडीबल ऑईल, शंकर फुडस्, वरूण फूडस् व कृषि उद्योग में स्वरूप उद्योग, जे पी इंडस्टीज, नंदन इंटरप्राईजेस आदि को अनुमति मिली है। यहां के निर्यातक उद्योग आरंभ होने से करोडों रूपए का रूका हुआ व्यवसाय पुनः आरंभ होगा वही 1250 श्रमिकों को भी अवसर मिलेगा। जिनके लिए उद्योगों ने खाने रहने की व्यवस्था की है।

उपाध्यक्ष योगेश मेहता ने उद्योगों के हित में की जा रही गतिविधियों की सक्षिप्त जानकारी दी। इस अवसर पर विजयवर्गीय ने कहा कि हमें कोरोना से बचाव के मार्ग पर स्वयं मंथन करना होगा। सामाजिक दूरी का पूर्ण ध्यान रखना व अपने जीवनशैली में बदलाव करना आवश्यक होगा। अपने श्रमिकों को प्रशिक्षित करना प्राथमिकता में होगा वही खान पान का पुरा ध्यान रखना होगा। विधायक ने उद्योगपतियों को बताया कि सांवेर रोड व आसपास के क्षेत्रीय गरीब जनता व श्रमिकों की भोजन सहायता की जा रही है तथा उन्हें प्रतिदिन भोजन के पैकेज पहुंचाये जा रहे है। आपने उद्योगों से आव्हान किया कि एसोसिएशन के माध्यम से उद्योगपति खाद्य तेल प्रदाय की सहायता करेगा तो यह भोजन व्यवस्था का कार्य ओर अधिक सुगमता से आगे बढ सकेगा। उद्योग जगत की सहायता से एसोसिएशन की ओर से 3000 लीटर खाद्य तेल इस पुनित कार्य के लिए प्रदान करने की घोषणा की गई। इस अवसर पर उपाध्यक्ष योगेश मेहता, सचिव सुनील व्यास, अमित धाकड़, सचिव तरूण व्यास, हरीश नागर, तपन जैन, अनील पालीवाल सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों व उद्योगपतियों की उपस्थिति थे।

प्लास्टिक उद्योगों को मिले उत्पादन की अनुमति

प्रतिनिधी मंडल ने सांसद, कलेक्टर से मिल कर की मांग

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

कोरोना संकट के चलते लॉक डाउन से उद्योग-कारखाने की आर्थिक समस्याओं से जुझना पड रहा है। प्लास्टिक उद्योग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। प्लास्टिक उद्योगों का प्रतिनिधि मंडल ने रेसीडेंसी कोठी पर सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह और एमपी एसआईडीसी के ईडी कुमार पुरूषोत्तम से मिला। इस दौरान प्लास्टिक उद्योग को प्रांरभ करने के लिए आवश्यक अनुमति देने सहित अनेक मुद्दों पर बात की गई।

बैठक में इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के अध्यक्ष सचिन बंसल, स्क्रैप एसोसिएशन से प्रकाश जैन , रिप्रोसेस ग्रेन्यूल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके माहेश्वरी आईपीपीएफ के सचिव रामकिशोर राठी,कोषाध्यक्ष विकास बांगड शामिल थे। सांसद लालवानी और अधिकारियों ने फैक्ट्री मालिकों व व्यापारीयों को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही उद्योगों की सुलभता के लिए निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब हम निरंतर परमिशन दे रहे है और आगे भी सरलीकरण करगें। उन्होंने उद्योगपतियों से थोड़ा संयम और सावधानी रखें का आग्र किया।

प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि इंदौर के सावेंर रोड औद्योगिक क्षेत्र में ही प्लास्टिक उद्योगों की संख्या 250 से अधिक है। यहां बनने वाले अधिकांश उत्पाद खाद्य सामग्री पैकिंग और इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग के निमार्ण करती है। यहां बनने वाले उत्पादों में फार्मास्युटिकल में लगने वाली आईवी फ्लूड चढने वाली बोटल, इंजेक्शन, मोल्डिंग मशीन, मोल्डिंग ढक्कन, शैंपु की बोतल, खाद्य में दुध के पाउच, पाउच रिप्रोसेस करने वाले, आइल केन बनाने वाले निर्माता शामिल है। वही आगामी मानसून के दौरान जरूरी तिरपाल जो कि अनाज को ढांकने, ट्रकों पर लगाने और घरों की छत पर डालने सहित अनेक कार्य के लिए जरूरी है।

पैकेज: छोटे उद्यमों को बिना गारंटी वाले 3 लाख करोड़ रुपये के कर्ज सुलभ कराने की पेशकश

नयी दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लघु उद्योगों के लिये बिना गारंटी वाले 3 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की सुविधा दिलाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने गैर-वेतन भुगतान पर कर कटौती में एक चौथाई राहत तथा गैर-बैंकिंग कंपनियों को नकदी की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराने की योजनाओं का भी ऐलान किया। इन उपायों का मकसद कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये जारी 'लॉकडाउन' से कंपनियों और इकाइयों को राहत देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना वायरस संकट से अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज के बारे में पहले चरण की जानकारी देते हुए सीतारमण ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 90,000 की नकदी बिजली वितरण कंपनियों को उपलब्ध करायी जाएगी ताकि उन्हें मौजूदा वित्तीय संकट से पार पाने में मदद मिले। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। इसके अलावा आयकर रिटर्न और अन्य रिटर्न भरने की तिथि भी बढ़ा दी गयी है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिना वेतन वाले भुगतान के लिये स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की दर में 31 मार्च 2021 तक के लिये 25 प्रतिशत की कटौती की गयी है। उन्होंने कहा कि इस कदम से इकाइयों के पास 50,000 करोड़ रुपये की नकदी बढ़ेगी। मंत्री ने 100 से कम कर्मचारी वाले कंपनियों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में योगदान से राहत की अवधि भी तीन महीने के लिये बढ़ा दी।साथ ही सभी कंपनियों के लिए ईपीएफ में कर्मचारियों के मूल वेतन के 12 प्रतिशत के बराबर सांविधिक योगदान करने की जगह इसे 10 प्रतिशत करने की छूट दी गयी है। इससे नियोक्ताओं के पास अतिरिक्त नकदी बचेगी। निर्माण क्षेत्र को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियां सभी ठेकेदारों को निर्माण और वस्तु एवं सेवा अनुबंधों को पूरा करने के लिये छह महीने की समयसीमा बढ़ाएंगी। सीमारमण ने कहा, "इस पैकेज से आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और एक आत्मनिर्भर भारत बनने का रास्ता साफ होगा...इसके जरिये कारोबार सुगमता, अनुपालन को आसान बनाया गया है तथा हमारा इरादा स्थानीय तौर पर बनने वाले उत्पादों को बढ़ावा देना भी है।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 'लॉकडाउन' से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिं 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) क लगभग 10 प्रतिशत है।एमएसएमई और अन्य छोटी इकाइयों के बारे में सीतारमण ने कहा कि बिना किसी गारंटी के कर्ज की सुविधा से 45 लाख लघु उद्यमों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कर्ज चार साल के लिये दिया जाएगा और 12 महीने तक किस्त से राहत दी जाएगी। इसके अलावा इस समय कर्ज नहीं चुका पा रही एमएसएमई इकाइयों के लिए भी कुल 20,000 करोड़ रुपये के कर्ज की सुविधा दी जाएगी। इससे 2 लाख इकाइयों को लाभ होगा। सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई के लिये 'फंड ऑफ फंड' गठित किया जा रहा है, इसके जरिये वृद्धि की क्षमता रखने वाले एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी डाली जाएगी।इसके साथ एमएसएमई की परिभाषा बदली गयी है। इसके तहत अब एक करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयां सूक्ष्म इकाई कहलाएंगी। अबतक यह सीमा 25 लाख रुपये थी। उन्होंने कहा कि इसके साथ एमएसएमई की परिभाषा के लिये कारोबार आधारित मानदंड बनाया गया है। इसके तहत 5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली इकाइयां भी सूक्ष्म इकाइयां कहलाएंगी। सीतारमण ने कहा कि लघु एवं मझोले उद्यमों के लिये निवेश और कारोबार सीमा बढ़ाने के जरिये उन्हें वित्तीय और अन्य लाभ उठाने की छूट दी गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि 200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद को लेकर वैश्विक निविदा पर पाबंदी होगी। इससे एमएसएमई को सरकारी निविदाओं में भाग लेने तथा और अधिक कारोबार हासिल करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और सूक्ष्म राशि के ऋण देने वाले संस्थानों (एमएफआई) के लिये मुश्किल के इस दौर में 30,000 करोड़ रुपये के विशेष नकदी योजना की भी घोषणा की। इसके अलावा निम्न साख रखने वाले एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिये 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी (पार्शियल क्रेडिट गारंटी) योजना 2.0 की भी घोषणा की। इस पहल का मकसद है कि ये कंपनियां व्यक्तियों तथा एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) क्षेत्र की इकाइयों को अधिक कर्ज दे सकें।

सरकार ने बदल दी MSME की परिभाषा

नई कैटिगरी के हिसाब से मिलेगा लाभ

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत MSMEs के लिए तमाम घोषणाएं की हैं। इसके अलावा श्एर्ई की परिभाषा भी बदल दी गई है। नई परिभाषा को जानना और समझना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जो घोषणाएं की गई हैं उसका फायदा उस कैटिगरी के हिसाब से मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं श्एर्ई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल ऐंड मीडियम एंटरप्राइजेज होता है। नई परिभाषा में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट को एक कैटिगरी में डाल दिया गया है। इसके अलावा उनका क्लासिफिकेशन इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, दोनों आधार पर किया गया है।

माइक्रो एंटरप्राइजेज

1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियां माइक्रो कैटिगरी में आएंगी। पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट की सीमा 25 लाख और सर्विस एंटरप्राइजेज के लिए इन्वेस्टमेंट की सीमा 10 लाख थी।

स्मॉल एंटरप्राइजेज

एक करोड़ से 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ से 50 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियां इस कैटिगरी में आएंगी। पुरानी परिभाषा में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के लिए इन्वेस्टमेंट की सीमा 25 लाख से 5 करोड़ तक थी। सर्विस एंटरप्राइजेज के लिए यह सीमा 10 लाख से 2 करोड़ तक थी।

मीडियम एंटरप्राइजेज

10-20 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट और 50-100 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियां इस कैटिगरी में आएंगी। पुरानी परिभाषा के तहत मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के लिए इन्वेस्टमेंट सीमा 5-10 करोड़ के बीच और सर्विस एंटरप्राइजेज के लिए यह सीमा 2-5 करोड़ के बीच है।

आत्मनिर्भर भारत

मजबूती के लिए छह कदमों का ऐलान

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) को मजबूती के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के कोलैटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि श्एर्ई, कुटिर उद्योगों और गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए छह नए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि एमएसमई सेक्टर के लिए 4 हजार करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी जिससे 2 लाख कंपनियों को फायदा होगा।

1. एमएसएमई और बिजनस के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के लिए कोलैटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन, 100%

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, कुटिर उद्योग और गृह उद्योग मिलकर 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपये का कोलैटरल फ्री ऑटोमैटिक लोन का प्रावधान किया गया है। किसी को अपनी ओर से किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इसकी समयसीमा भी चार वर्ष की होगी। पहले एक वर्ष में मूलधन वापस नहीं करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर, 2020 से इस स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेकर 45 लाख यूनिट बिजनस ऐक्टिविटी दोबारा शुरू कर सकते हैं और उनके यहां नौकरियां बचाई जा सकती हैं।

2. एमएसएमई के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का सबॉर्डिनेट डेट

एनपीए वाले और स्ट्रेस्ड MSMEs को 20 हजार करोड़ रुपये का सबॉर्डिनेट लोन दिया जाएगा। इससे 2 लाख से ज्यादा यूनिट को लाभ मिलेगा।

3.एमएसएमई फंड ऑफ फंड्स के जरिए 50 हजार करोड़ रुपये का इक्विटी इन्फ्यूजन

जो MSME अच्छा कर रहे हैं और वो बिजनस का विस्तार करना चाहते हैं, अपना आकार और क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए फंड ऑफ फंड्स के जरिए फंडिंग मिलेगी।

4. MSME की परिभाषा बदली गई

MSME के हित में इसकी परिभाषा बदल दी गई है। ये बदलाव मैन्युफैक्चिरिंग और सर्विस, दोनों इंडस्ट्रीज पर लागू होंगे...

1 करोड़ रुपये तक निवेश करके 5 करोड़ तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री सूक्ष्म

10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक व्यापार करने वाली इंडस्ट्री लघु

जबकि 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ रुपये तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री मध्यम कहलाएगी।

5.200 करोड़ रुपये के लिए ग्लोबल टेंडर की अनुमति नहीं

200 करोड़ रुपये तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर की अनुमति नहीं होगी। सरकार को घरेलू कंपनियों से टेंडर मंगवाने की बाध्यता होगी। इससे 'लोकल के लिए वोकल' के मंत्र को मजबूती मिलेगी। स्थानीय उत्पादों और सेवाओं।

6. अन्य उपाय

MSMEs को ई-मार्केट लिंकेज किया जाएगा।

ट्रेड फेयर में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास उनका बकाया है तो अगले 45 दिनों में बकाया भुगतान करवाने की कोशिश की जाएगी।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज

सरकार की एक साल की कुल कमाई से भी ज्यादा हैं 20 लाख करोड़ रुपये

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस से पीड़ित अर्थव्यवस्था के इलाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज (AatmaniRhar Bharat Economic Package) की घोषणा की है, वह सरकार की 1 साल की कुल राजस्व कमाई से भी ज्यादा है। इस समय साल भर में सरकार का कुल टैक्स रेवेन्यू 15 लाख करोड़ रुपये (India's total tax revenue) के करीब आ रहा है। इसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू (Non-Tax Revenue) के 3.45 लाख करोड़ रुपये को भी जोड़ दिया जाए, तो भी इतने पैसे नहीं होते हैं। हालांकि चालू वित्त वर्ष के बजट में तो 20 लाख करोड़ से भी ज्यादा की राजस्व आमदनी का अनुमान लगाया गया है, लेकिन इसका पूरा होना मुश्किल दिखता है।

कहां से आता है पैसा

वित्त वर्ष 2019-20 की आमदनी के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस साल सरकार को प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर से कुल मिलाकर 15.04 लाख करोड़ रुपये आए। इसमें से ज्यादातर हिस्सा मतलब 11 लाख करोड़ रुपये से कुछ ज्यादा कारपोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स के मद में आए। पिछले साल कस्टम ड्यूटी मद में सवा लाख करोड़ रुपयेऔर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी मद में करीब ढाई लाख करोड़ रुपये आए। 1200 करोड़ रुपये सर्विस टैक्स के रूप में मिले जबकि जीएसटी के रूप में 6.12 लाख करोड़ रुपये मिले। 6884 करोड़ रुपये केंद्र शासित प्रदेशों के टैक्स से सरकार को मिले। लेकिन इस राशि में से 6.56 लाख करोड़ रुपये राज्यों का हिस्सा भी गया। इस तरह से केंद्र सरकार के हाथ में बचे 15.04 लाख करोड़ रुपये।

नॉन टैक्स रेवेन्यू की भी अच्छी हिस्सेदारी

आलोच्य अवधि में सरकार को नॉन टैक्स रेवेन्यू मद में भी 3.45 लाख करोड़ रुपये मिले। इस दौरान केंद्र सरकार की कंपनियों से डिविडेंड और प्रॉफिट के रूप में करीब दो लाख करोड़ रुपये मिले तो other non tax रेवेन्यू के मद में 1.32 लाख करोड़ रुपये मिले। सरकार को इंटरेस्ट रिसीट मद में भी 11027 करोड रुपये मिले। इसके अलावा कुछ और नॉन टैक्स रिवेन्यू मिले जो कि केंद्र शासित प्रदेशों से आए थे। टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों को मिला दें तो यह 18.50 करोड़ रुपये से थोड़ा सा ज्यादा होता है।

शेष जुटाना पड़ता है बाजार उधारी के जरिए

टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू के अलावा जो भी राशि बचती है उसे कैपिटल रिसिट के जरिए जुटाना पड़ता है। पिछले साल का बजट करीब 27 लाख करोड़ रुपये का था, जबकि टैक्स और नॉन टैक्स रिवेन्यू से 18.50 लाख करोड़ रुपये आए। मतलब 848000 करोड़ रुपये कैपिटल रिसिप्ट के जरिए जुटाए गए। कैपिटल रिसिट में अधिकतर हिस्सेदारी बाजार से उधारी की होती है।

इस साल 31 लाख करोड़ रुपये का बजट

चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने 30 लाख 95 हजार करोड़ रुपये का बजट बनाया है, जिनमें से रेवेन्यू रिसिट से 16 लाख 35 हजार करोड़ रुपये जुटाने का अनुमान है। टैक्स रेवेन्यू की स्थिति को देखते हुए सरकार ने कुछ दिन पहले ही तय किया है कि इस बार बाजार उधारी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ली जाएगी।

बड़ी कामयाबी

127 देशों में कोरोना की दवा बेचेगी भारतीय कंपनी

अमेरिकी कंपनी से किया करार

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना वायरस के प्रभावी इलाज की दिशा में भारत की तीन दिग्गज दवा कंपनियों ने बड़ी पहल की है। देश की दिग्गज दवा निर्माता कंपनियों जुबिलंट लाइफ साइंसेज, हेटेरो तथा सिप्ला ने अमेरिकी दवा कंपनी गिलियड के साथ मिलकर कोरोना वायरस के इलाज में कारगर मानी जानी वाली दवा रेमडेसिवीर बनाने के लिए एक करार किया है। यह समझौता भारत तथा 127 अन्य लो, मिडिल तथा अपर मिडिल इनकम वाले देशों के लिए है, जहां नोएडा की कंपनी दवा की मार्केटिंग करेगी।

भारतीय कंपनी तय करेगी कीमत

गिलियड ने एक बयान में बताया कि लाइसेंसिंग अग्रीमेंट के तहत, करार में शामिल कंपनियों के पास गिलियड से रेमडेसिवीर बनाने की प्रक्रिया का टेक्नॉलजी ट्रांसफर पाने का अधिकार होगा, जिससे उसका उत्पादन तेजी से हो सकेगा। कंपनी ने यह भी कहा है कि जो लाइसेंसी कंपनियां जेनरिक प्रॉडक्ट बनाएंगी, उसकी कीमत तय करने का अधिकार उन्हीं के पास होगा।

कंपनियों को होगा बड़ा फायदा

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जबतक कोविड-19 को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति की घोषणा नहीं करती है, तब तक लाइसेंस रॉयल्टी-मुक्त होते हैं या कोरोना महामारी को रोकने के लिए रेमडेसिविर के बजाय कोई अन्य औषधि उत्पाद या वैक्सिन को मंजूरी नहीं मिल जाती है, या दोनों में से जो पहले होता है।

देश में कीमत कम करने पर जोर

जुबिलंट लाइफ साइंसंज के चेयरमैन श्याम भरतिया तथा मैनेजिंग डायरेक्टर हरी एस. भरतिया ने एक बयान में कहा, 'हम दवा के क्लीनिकल ट्रायल्स तथा नियामकीय मंजूरी पर बेहद करीबी नजर रखेंगे और नियामकीय मंजूरी मिलने के तुरंत बाद दवा को लॉन्च करने की तैयारी करेंगे। हमारी योजना देश में ही दवा के ऐक्टिव फार्मास्यूटिक इनग्रेडियंट (API) को तैयार करने की है, जिससे न सिर्फ इसकी कीमत कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि उसकी उपलब्धता भी निरंतर होगी।'

देश में कंप्यूटरों की बिक्री 2020 की पहली तिमाही में 17 प्रतिशत गिरी : आईडीसी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

देश में कंप्यूटरों की बिक्री 2020 की जनवरी-मार्च तिमाही में सालाना आधार पर 16.7 प्रतिशत गिर गयी। इस दौरान देश में 18 लाख कंप्यूटर की बिक्री हुई। शोध कंपनी आईडीसी की रपट के अनुसार बिक्री में यह गिरावट सभी श्रेणियों में रही। इसकी प्रमुख वजह कोविड-19 संकट की वजह से आपूर्ति श्रृंखला का बाधित होना है। इसकी वजह से चीन में विनिर्माण और लॉजिस्टिक प्रभावित हुआ। पिछले साल जनवरी-मार्च तिमाही में देश में 21 लाख कंप्यूटर की बिक्री हुई थी। कंप्यूटरों की इस बिक्री में डेस्कटॉप, लैपटॉप और कामकाजी कंप्यूटर शामिल हैं। आईडीसी ने कहा कि देश में मार्च के दौरान लॉकडाउन (पाबंद) की वजह से कंप्यूटर की खुदरा और वाणिज्यिक बिक्री लगभग पूरी तरह ठप रही। लैपटॉप श्रेणी की बिक्री सालाना आधार पर 16.8 प्रतिशत गिर गयी।

जितना ज्यादा निवेश, उतने ज्यादा समय के लिए मिलेगी टैक्स छूट!

नई दिल्ली। एजेंसी

सरकार अब जल्द से जल्द देश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाना चाहती है, ताकि इकॉनमी की गति को फिर से पटरी पर लाया जा सके। कामकाज शुरू होगा तो नौकरियों के अवसर भी मार्केट में आएंगे। इसके लिए जरूरी है कि देश में निवेश को बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार एक मेगा प्लान पर काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार नए निवेश करने वाली कंपनियों को टैक्स हॉलिडे यानी कर अवकाश देने की तैयारी में है। हालांकि टैक्स हॉलिडे लेने के लिए कंपनियों को कई शर्तों का पालन करना होगा। इनमें सबसे अहम शर्त है कि यह छूट नए निवेश पर मिलेगी। शर्तें हैं... कंपनियों को भारत में 1 जून से तीन साल के भीतर अपना कारोबार शुरू करना होगा। इस छूट का फायदा उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जो मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलिकॉम इक्विपमेंट और कैपिटल गुड्स सेगमेंट में कारोबार शुरू करेंगी। इसके बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा, वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे पारित किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, निवेश राशि के अनुसार टैक्स हॉलिडे देने की अवधि तय की जाएगी। यानी जितना ज्यादा निवेश, उतने ज्यादा समय के लिए टैक्स हॉलिडे की सुविधा।

क्या है प्रस्ताव?

सूत्रों के अनुसार, मौजूदा समय में जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, उसके तहत 50 करोड़ डॉलर तक का निवेश हासिल करने वाली कंपनियों को फाइनैंस मिनिस्ट्री 10 साल टैक्स छूट दे सकती है। इसके साथ ही उन कंपनियों को 4 साल तक टैक्स से छूट दिए जाने पर विचार हो रहा है जो 10 करोड़ डॉलर तक का निवेश भारत में उन सेक्टरों में करेंगी, जिनमें मजदूरों की जरूरत ज्यादा होती है। इनमें टेक्सटाइल्स सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग, लेदर और फुटवियर शामिल हैं। इसके अलावा, अगले 6 साल के लिए 10 फीसदी कॉरपोरेट टैक्स लगाने का प्रस्ताव है, ताकि कंपनियों पर बोझ कम हो सके।

कामकाज के साथ रोजगार बढ़े

सरकार आर्थिक कामकाज बढ़ाने के साथ मार्केट में रोजगार के अवसर भी बढ़ाना चाहती है। एक अनुमान के अनुसार, लॉकडाउन की वजह से अप्रैल में करोड़ों लोगों की नौकरी जा चुकी है। इसके अलावा, सरकार की नजर उन विदेशी कंपनियों पर है, जो चीन छोड़ने की तैयारी में हैं। सरकार इन कंपनियों को भारत लाना चाहती है। साथ ही सरकार, भारतीय कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है।

ज्यादा श्रमिक वाले सेक्टरों पर जोर

BMC के महासचिव विरजेश उपाध्याय के अनुसार, हमने सरकार से आग्रह किया था कि उन सेक्टरों में सबसे पहले निवेश बढ़ाने की कोशिश की जाए, जिनमें श्रमिकों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। दरअसल, लॉकडाउन का असर छोटे उद्योगों और कारोबारियों पर ज्यादा पड़ा है और इससे श्रमिक वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अगर सरकार टेक्सटाइल्स और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश बढ़ाएगी तो इसका फायदा श्रमिक वर्ग को भी मिलेगा। यही इस वक्त की जरूरत है। सरकार का पूरा जोर श्रमिक को फिर रोजगार दिलाने पर होना चाहिए।

हवन में 'स्वाहा' क्यों बोलते हैं, जानिए रहस्य...

वास्तव में अग्नि देव की पत्नी हैं स्वाहा। इसलिए हवन में हर मंत्र के बाद होता है इनका उच्चारण। जानिए विस्तार से...

स्वाहा का अर्थ है: सही रीति से पहुंचाना। दूसरे शब्दों में कहें तो जरूरी पदार्थ को उसके प्रिय तक सुरक्षित पहुंचाना। श्रीमद्भागवत तथा शिव पुराण में स्वाहा से संबंधित वर्णन आए हैं। मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा कहकर ही

हवन सामग्री भगवान को अर्पित करते हैं। हवन या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में मंत्र पाठ करते हुए स्वाहा कहकर ही हवन सामग्री, अर्घ्य या भोग भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन, कभी आपने सोचा है कि हर मंत्र के अंत में बोले जाने वाले शब्द स्वाहा का अर्थ क्या है। दरअसल कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जा सकता है जब तक कि हवन का ग्रहण देवता न कर लें। लेकिन, देवता ऐसा ग्रहण तभी कर सकते हैं जबकि अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पण किया जाए। श्रीमद्भागवत तथा शिव पुराण में स्वाहा से संबंधित वर्णन आए हैं। इसके अलावा ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वैदिक ग्रंथों में अग्नि की महत्ता पर अनेक सूक्तों की रचनाएं हुई हैं।

पौराणिक कथा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, स्वाहा दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। इनका विवाह अग्निदेव के साथ किया गया था। अग्निदेव अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही हविष्य ग्रहण करते हैं तथा उनके माध्यम से यही हविष्य आह्वान किए गए देवता को प्राप्त होता है। वहीं, दूसरी पौराणिक कथा के मुताबिक अग्निदेव की पत्नी स्वाहा के पावक, पवमान और शुचि नामक तीन पुत्र हुए। स्वाहा की उत्पत्ति से एक अन्य रोचक कहानी भी जुड़ी हुई है। इसके अनुसार, स्वाहा प्रकृति की ही एक कला थी, जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के आग्रह पर संपन्न हुआ था। भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं स्वाहा को ये वरदान दिया था कि केवल उसी के माध्यम से देवता हविष्य को ग्रहण कर पाएंगे। यज्ञीय प्रयोजन तभी पूरा होता है जबकि आह्वान किए गए देवता को उनका पसंदीदा भोग पहुंचा दिया जाए।

मंगल कार्यों में नारियल क्यों फोड़ा जाता है?

चाहे पूजा हो या नए घर का गृह प्रवेश, नई गाड़ी या नया बिज़नेस किसी भी कार्य का शुभारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। नारियल को भारतीय सभ्यता में शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसलिए पूजा-पाठ और मंगल कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। हिंदू परंपरा में नारियल सौभाग्य और समृद्धि की निशानी होती है। नारियल भगवान गणेश को चढ़ाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। नारियल इस धरती के सबसे पवित्र फलों में से एक है। इसलिए इस फल को लोग भगवान को चढ़ाते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों आखिर किसी भी काम को शुरू करने से पहले नारियल क्यों फोड़ा जाता है। ऋषि विश्वामित्र को नारियल का निर्माता माना जाता है। इसकी ऊपरी सख्त सतह इस बात को दर्शाती है कि किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी होती है। नारियल एक सख्त सतह और फिर एक नर्म सतह होता है और फिर इसके अंदर पानी होता है जो बहुत पवित्र माना जाता है। इस पानी में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। नारियल भगवान गणेश का पसंदीदा फल है। इसलिए नया घर या नई गाड़ी लेने पर फोड़ा जाता है। इसका पवित्र पानी जब चारों तरफ फैलता है तो नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। नारियल तोड़ने का मतलब अपने अहम को तोड़ना है। नारियल इंसान के शरीर को प्रदर्शित करता है और जब आप इसे तोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आपने खुद को ब्रह्मांड में सम्मिलित कर लिया है। नारियल में मौजूद तीन चिन्ह, भगवान शिव की आंखें मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि यह आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करता है। नारियल को संस्कृत में 'श्रीफल' कहा जाता है और श्री का अर्थ लक्ष्मी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, लक्ष्मी के बिना कोई भी शुभ काम पूर्ण नहीं होता है। इसीलिए शुभ कार्यों में नारियल का इस्तेमाल अवश्य होता है। नारियल के पेड़ को संस्कृत में 'कल्पवृक्ष' भी कहा जाता है। 'कल्पवृक्ष' सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। पूजा के बाद नारियल को फोड़ा जाता है और प्रसाद के रूप में सब में वितरित किया जाता है।

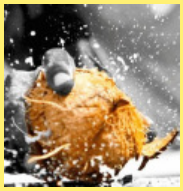

13 मई-25 जून शुक्र वक्री रहेंगे

आपका जीवन कितना प्रभावित होगा

जीवन में प्रेम, कला, सौंदर्य और ऐश्वर्या आदि के कारक ग्रह शुक्र 13 मई 2020 से वक्री हो जाएंगे और लगातार 25 जून 2020 तक वक्री रहेंगे। निश्चित रूप से इस दौरान वह सभी 12 राशियों को प्रभावित करेंगे। शुक्र ग्रह की उल्टी चाल आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगी, यहां पढ़िए:-

मेष राशि पर वक्री शुक्र का प्रभाव

शुक्र के दूसरे भाव में वक्री होने से आपकी धन की बचत होगी।
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
आपकी वाणी में मधुरता आएगी, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे।
घर का वातावरण भी शांतिपूर्ण रहेगा।
पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे।

वृष राशि पर वक्री शुक्र का प्रभाव

शुक्र आपकी राशि में वक्री हो रहा है। वृष शुक्र की स्वराशि है।
इस दौरान आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है।
इस दौरान आपको कई क्षेत्र में लाभ होगा और परिवार का भी सहयोग मिलेगा।
पारिवारिक जीवन में सुख का अनुभव करेंगे।

मिथुन राशि पर वक्री शुक्र का प्रभाव

शुक्र का द्वादश भाव में होना आपके लिए शुभ हो सकता है।
इस दौरान आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी।
यह वक्री पारिवारिक जीवन के लिए काफी शुभ है।
जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर होंगे।

कर्क राशि पर वक्री शुक्र का प्रभाव

शुक्र का वक्री आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है।
व्यापार से अच्छी खबर मिल सकती है।
हालांकि इस दौरान अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। खासकर यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो।

सिंह राशि पर वक्री शुक्र का प्रभाव

इस दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए धन संभालकर खर्च करें। वरना आपका आर्थिक बजट गड़बड़ा सकता है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना आपके लिए जरूरी है।

कन्या राशि पर वक्री शुक्र का प्रभाव

शुक्र का आपके नवम भाव में होना शुभ है।
इस दौरान आपके भाग्य में वृद्धि होने की संभावना है।
गुरुजनों का सम्मान प्राप्त होगा।
पारिवारिक मतभेद दूर होंगे।

तुला राशि पर वक्री शुक्र का प्रभाव

शुक्र वक्री के प्रभाव से आपको उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको धन अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और कार्यक्षेत्र में भी बाधाएं आ सकती हैं।

वृश्चिक राशि पर वक्री शुक्र का प्रभाव

आपके दांपत्य जीवन में वक्री शुक्र खुशियां लेकर आएगा।
जीवनसाथी से रिश्ते मधुर होंगे।
सरकार द्वारा आपको लाभ होगा।
निवेश से अभी दूर रहें। यह समय निवेश के लिए सही नहीं है।

धनु राशि पर वक्री शुक्र का प्रभाव

अपनी सेहत का ख्याल रखें।
शत्रु आपके ऊपर हावी होंगे। उनकी चाल से बचें। कार्यक्षेत्र के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय होगा।
इस समय आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

मकर राशि पर वक्री शुक्र का प्रभाव

शुक्र का पंचम भाव में होना आपके प्रेम जीवन में ताजगी भरेगा।
इस दौरान अपनी भावनाओं पर काबू रखें।
इस दौरान आपको संतान की तरफ से लाभ होगा।
जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करने से रिश्ते में मधुरता आएगी।
पारिवारिक सुख का अनुभव करेंगे।

कुंभ राशि पर वक्री शुक्र का प्रभाव

इस दौरान आपके घर में खुशियां आ सकती है।
घर के परिजनों में एकता और भाईचारा व प्रेम का भाव बढ़ेगा।
माता जी की सेहत दुरुस्त होगी।
प्रेम जीवन में सुख का अनुभव करेंगे।
पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे।

मीन राशि पर वक्री शुक्र का प्रभाव

इस दौरान आपको अपने आत्मबल को मजबूत करने की आवश्यकता होगी।
मन में किसी तरह का नकारात्मक विचार न लाएं।
छोटे भाई-बहनों के साथ किसी तरह का विवाद हो सकता है।
इस समय सबके साथ प्रेमपूर्वक रहने में ही भलाई है।

तुलसी के पौधे से बड़ा लाभ

पुराणों में लिखा है कि तुलसी पूजा रोज की जाना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे को जल देने से लाभ होता है। वहीं शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप दीपक लगाया जाता है। प्रतिदिन तुलसी के पौधे की आराधना से मां तुलसी की कृपा बरसती है। तुलसी माता की पूजन से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। घर में तुलसी के पौधे की रोज पूजन से घर के वास्तु दोषों और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। परिवार की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आता है। घर में व्याप्त नाकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। आपके घर में तुलसी का पौधा कभी भी सूखना नहीं चाहिए, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि तुलसी के पौधे को समय-समय पर पानी मिलता रहे। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में सूखता या मुरझा जाता है तो आप और आपके परिवार को कई प्रकार की समस्याओं के सामना करना पड़ सकता है।

ऐसी समस्याओं से बचने के लिए तुलसी माता के पौधे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी तरक्की पर कभी कोई असर नहीं होगा। तुलसी माता आपके घर में स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार भी स्वस्थ और खुशहाल रहेगा।

तुलसी का पौधा आपके घर में हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरुरी है। दरअसल पूजन-आराधना के लिए तुलसी हम रोज तोड़ते हैं, लेकिन तुलसी तोड़ने के लिए भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरुरी है। तुलसी को तोड़ते समय आप अगर अपवित्र हैं, तो नहीं तोड़ें। एकादशी, रविवार और चंद्रग्रहण के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है। बगैर जरुरत के भी तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी माता का अपमान होता है। तुलसी की खुशबू सांस संबंधित कई बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। तुलसी की एक पत्ती का रोज सेवन करना चाहिए। बुखार, सर्दी जैसी बीमारियों के समय तुलसी के पत्ते की चाय बनाने से भी लाभ मिलता है। तुलसी का नियमित सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में भी मदद करता है।

भारतीय सीमा पर चीनी सेना की हरकतों के पीछे है 1,000 कंपनियों के खोने का डर!

नई दिल्ली। एजेंसी

कोरोना महामारी के दौर में भी चीन का अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को बढ़ावा एक सोची-समझी रणनीति के तहत कर रहा है। माना जा रहा है कि कोविड-19 महामारी में कमी आने के बाद चीन को निवेशकों के पड़ोसी देशों में पलायन का डर है और उसी से पेइचिंग बौखलाया हुआ है। चीन ऐसे हथकंडे अपना कंपनियों को बाहर जाने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है।

चीन की हरकत के पीछे निवेश खोने का डर

अगर चीन की इस हरकतों को समझने की कोशिश की जाए तो वह अपनी सेना का इस्तेमाल भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान और मलेशिया के खिलाफ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि एशिया में कोई अन्य ऐसा देश नहीं है जहां निवेशक जा पाएं। चीन में काम रहीं 1,000 कंपनियां कई देशों के साथ बातचीत भी कर रही हैं।

भारत से लेकर इंडोनेशिया, सबसे भिड़ रहा चीन

पिछले तीन सप्ताह के दौरान लद्दाख और सिक्किम में चीनी सेना से झड़प और गालवान नदी के करीब भारतीय और चीनी सेना के बीच तनातनी देखी गई है। हालांकि, दोनों देशों के सैनिकों को बीच अनिर्णीत सीमा पर कभी-कभार झड़प होती रही है लेकिन एक ही वक्त में दो राज्यों की सीमा के करीब चीनी सेना की हरकत असामान्य है। इस बात का भी शक की है विवादित लिपुलेख दर्रे के करीब सड़क पर नेपाल के साथ विवाद को भी पेइचिंग का मौन समर्थन हो। साउथ चाइन सी में चीन के नौसेना आक्रामक अभ्यास किया जा रहा है। चीनी तटरक्षकों के हमले में वियतनाम की मछली मारने की एक नाव ध्वस्त हो गई। इसके अलावा चीन का टोही जहाज इंडोनेशिया के करीब देखा गया है।

चीन को है 1,000 कंपनियों का डर!

भारत चीन की सीमा पर इस आक्रमकता को उसके यहां से निवेश खिसकने का डर मान रहा है। 1,000 कंपनियां कोविड-19 के प्रकोप में कमी आने के बाद चीन से अपना कारोबार समेटकर भारत और अन्य देशों में निवेश करना चाहती है और वे इसके लिए इन देशों से बात भी कर रही हैं।

कंपनियों को लुभा रहे हैं भारत और वियतनाम

चीन से बाहर निकलने वाली कंपनियों के लिए भारत बेहतर माहौल मुहैया कराने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसके अलावा वियतनाम के पास पहले भी बाजार पर कब्जा करने का हुनर रहा है। चीन से निकलने वाले निवेशकों के लिए इंडोनेशिया भी एक बेहतर जगह हो सकती है। इंडोनेशिया सरकार ने चीनी फीशिंग कंपनियों के अपने नागरिकों के साथ गुलामों वाला व्यहार की निंदा की है। चीनी कंपनियों के खराब व्यवहार के कारण इंडोनेशिया के 3 लोगों की मौत भी हुई है। इस मुद्दे के कारण चीन और इंडोनेशिया के बीच तनाव और बढ़ सकता है। सूत्रों ने बताया कि इस तरह की दबाव की रणनीति बनाकर चीन खुद को ही परेशानी में डाल रहा है क्योंकि दुनिया अब पेइचिंग पर निर्भरता कम करने की रणनीति की तरफ देख रही है।

उद्योग जगत ने कहा

प्रोत्साहन पैकेज से अर्थव्यवस्था को कोरोना संकट से पार पाने में मदद मिलेगी

नयी दिल्ली। एजेंसी

उद्योग जगत ने बुधवार को वित्त मंत्री के एमएसएमई, वितरण कंपनियों और रीयल एस्टेट क्षेत्र को ध्यान में रखकर लाये गये प्रोत्साहन पैकेज की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे कंपनियों और अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस संकट के प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी। उद्योग मंडलों ने कहा कि इन उपायों से बाजार में नकदी बढ़ेगी और संकट में फंसे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को नया जीवन मिलेगा। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने और उसे पटरी पर लाने के लिये बुधवार को करीब 6 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की। इसमें सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों समेत छोटे कारोबारियों को 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी वाला कर्ज उपलब्ध कराने और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) तथा आवास वित्त कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये की नकदी सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। यह पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा का हिस्सा है। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि आज की घोषणा की सबसे महत्वपूर्ण बात एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव है। इसका दीर्घकालीन और व्यापक प्रभाव पड़ेगा। एमएसएमई विकास कानून, 2006 के बाद से इसमें बदलाव नहीं किया गया था और इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि इन उपायों से एमएसएमई, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, आवास वित्त कंपनियों, दबाव वाली रीयल एस्टेट कंपनियों और निर्माण क्षेत्र को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को चार साल के लिये 3 लाख करोड़ रुपये का बिना गारंटी का कर्ज और एक साल के लिये मूल राशि लौटाने से छूट, इस क्षेत्र को पटरी पर लाने की दिशा में बड़ा कदम है। यह इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि इसमें 11 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है जबकि देश के जीडीपी में इसका 30 प्रतिशत योगदान है। फिक्की की अध्यक्ष संगीता रेड्डी ने प्रोत्साहन पैकेज-2 का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार के अन्य उपायों को लेकर भी उनका रुख सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि इस व्यापक प्रोत्साहन उपायों की घोषणा से भारतीय उद्योग और अर्थव्यवस्था को गति मिलने का मंच तैयार हो गया है।

वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में 31 देशों से होगी 30,000 भारतीयों की स्वदेश वापसी : पुरी

नयी दिल्ली। एजेंसी

नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में 31 देशों से 30,000 भारतीयों की स्वदेश वापसी होगी। इसके लिए 16 मई से 22 मई के बीच 149 विमानों का संचालन किया जाएगा। वंदे भारत मिशन के पहले चरण में एअर इंडिया और उसकी अनुषंगी एअर इंडिया एक्सप्रेस सात मई से 14 मई के बीच 64 विमानों का परिचालन किया। इसके तहत 12 देशों से 14,800 भारतीयों को स्वदेश वापस लाया गया है। हालांकि, इसके लिए उनसे किराया वसूला गया है।कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशभर में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है। इसके चलते सभी वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन बंद है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 74,200 का आंकड़ा पार कर चुकी है जबकि 2,400 से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है।

लॉकडाउन: ब्रिटेन का जीडीपी दो प्रतिशत गिरा

लंदन। एजेंसी

ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 2020 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर दो प्रतिशत प्रतिशत संकुचित हुई। यह स्पष्ट तौर पर कोरोना वायरस लॉकडाउन (बंद) के अर्थव्यवस्था पर असर को दिखाने वाला आंकड़ा है। वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद किसी तिमाही में यह देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ओएनएस) ने बुधवार को इस संबंध में आधिकारिक आंकड़े जारी किए। ओएनएस ने कहा, "अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का असर साफ दिखता है। मार्च में समाप्त तिमाही में लगभग सभी उप-क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की गयी।" आंकड़ों के मुताबिक देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अकेले मार्च में 5.8 प्रतिशत की गिरावट आयी। यह अब तक की सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। वहीं तिमाही आधार पर यह 2008 के आर्थिक संकट के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। वर्ष 2019 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में ब्रिटेन की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रही थी, क्योंकि ब्रिटेन के सेवाक्षेत्र में रिकॉर्ड गिरावट देखी गयी थी। ओएनएस के आंकड़ों के मुताबिक समीक्षावधि में देश के सेवा क्षेत्र में 1.9 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी है जो कुल जीडीपी का करीब 80 प्रतिशत है। इस दौरान उत्पादन में 2.1 प्रतिशत और निर्माण में 2.6 प्रतिशत की गिरावट रही। यह आंकड़े मंदी के रूख को दिखाते हैं, यदि दो तिमाहियों में लगातार यह गिरावट रहती है तो देश की अर्थव्यवस्था में मंदी होगी। यह आंकड़े ब्रिटेन के भारतीय मूल के वित्त मंत्री ऋषि सुनक की कोरोना वायरस नौकरी संरक्षण योजना को अक्टूबर तक बढ़ाए जाने की घोषणा के एक दिन बाद आए हैं। इसके तहत कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा जा सकता है और सरकार इसके लिए अनुदान देगी। सुनक इंफोसिस के संस्थापक एन. नारायण मूर्ति के दामाद हैं।

वाहनों पर जीएसटी दर में कटौती का सही समय नहीं : मारुति

नयी दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को कहा कि वाहनों पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) की दर कम करने का यह सही समय नहीं है। इससे कुछ लाभ नहीं होगा क्योंकि वाहन उद्योग का उत्पादन इस समय सबसे निचले स्तर पर है। घरेलू यात्री वाहन बाजार में करीब 54 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाली मारुति ने कहा कि यदि कर की दर में किसी तरह की कटौती प्रस्तावित भी है, तो उसे सही समय पर किया जाना चाहिए। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर. सी. भार्गव ने यहां एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, "अभी हम जिस स्थिति में है, वैसे में अगले एक-दो महीने तक सभी वाहन कंपनियों का उत्पादन बहुत निचले स्तर पर रहेगा। ऐसे में जीएसटी कर की दर में कटौती का कोई औचित्य नहीं।" उनसे इस संबंध में प्रश्न किया गया था कि कोरोना वायरस महामारी संकट से प्रभावित वाहन उद्योग के लिए जीएसटी कर की दर में कटौती का क्या यह सही समय है। भार्गव ने कहा कि जीएसटी कर की दर में कटौती तभी उचित होगी जब वाहनों की आपूर्ति मांग की तुलना में अधिक होगी और उत्पादन को वास्तव में उच्च स्तर तक बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने कहा, "तभी इसका (जीएसटी कटौती) कोई लाभ होगा। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इसे निश्चित तौर पर तत्काल करने की कोई जरूरत नहीं है।"

Authorised Dealer of

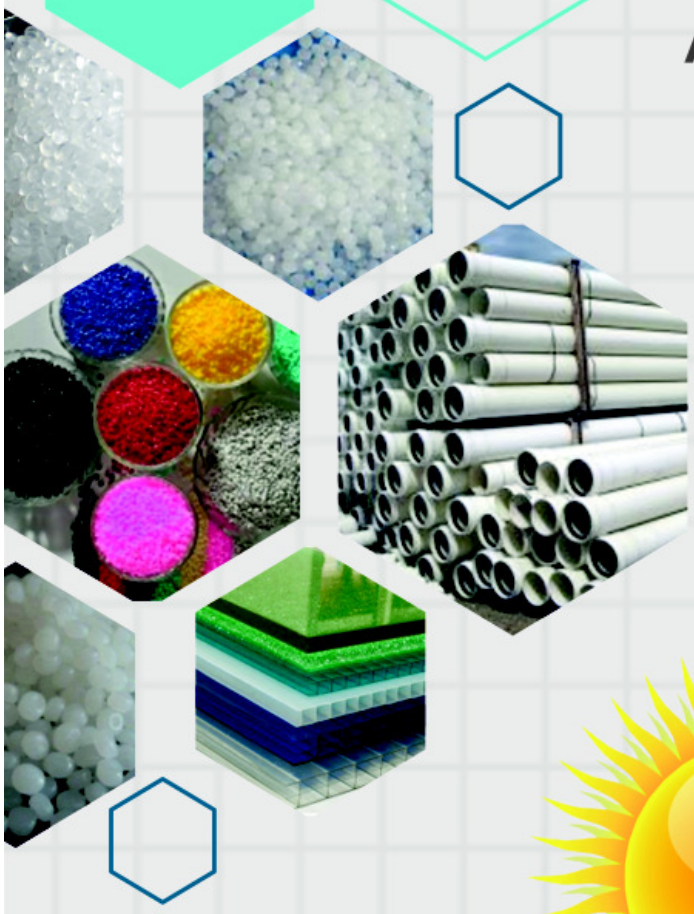

Reliance
POLYMERS

Bhaskar Resins Pvt Ltd

DEALER : RELIANCE INDUSTRIES LTD

44 D-2, Sanwer Road Industrial Area, Sector D, Railway Crossing Main Rd, Indore, Madhya Pradesh 452015
website- http://bhaskarresins.com
email- bhaskarresins12@gmail.com

Mob- +91-96307-98864
Tel : 0731 -2971277, 2971377
email- sachinbansal123@gmail.com

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।